राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 155

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 13 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

एक वाइड ने छीनी चाहर से दूसरी हैट्रिक >> 14

BYJU'S The Learning App
IAS 2020

IAS 2020 के लिए
निःशुल्क कार्यशाला
DATE : 17TH NOVEMBER 2019 (SUNDAY) | TIME : 4:30 PM

भारतीय राजव्यवस्था के साथ बैच प्रारम्भ
25TH NOVEMBER 2019
8.00 PM TO 7.30 PM

DEMO CLASS AVAILABLE FROM 18TH NOVEMBER 2019
8.00 PM TO 7.30 PM

कार्यालय का पता : Shop No. 15, Ground Floor, Vardhman Central Mall, Nehru Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi-54

9205881869

सरोकार

'ग्रामोफोन' से बदल रहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाल

इंदौर : मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में ग्रामोफोन स्टार्टअप न केवल किसानों को बचत की

राह दिखा रहा है, वरन कृषिभूमि को रसायनों की मार से भी बचाने का काम कर रहा है। तीन साल में छह लाख रुपये से शुरू हुआ स्टार्टअप 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। (पेज-11)

जागरण विशेष

दुश्मन को 'घर में घुसकर मारेंगे' आइबीजी के लड़ाके

जम्मू : सेना का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (आइबीजी) आदेश के 12 घंटे के भीतर ही

दुश्मन को घर में घुसकर ढेर कर देगा। यही इसकी विशेष दक्षता है। इस माह के अंत तक जम्मू से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास होने जा रही है तैनाती। (पेज-11)

अयोध्या पर विशेष पेज

अयोध्या लाइव >> 4
फैसले के बाद >> 5

न्यूज गैलरी

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

गुरु नानक साहिब पूरी मानवता की साझी धरोहर : कोविंद

सुल्तानपुर लोधी : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को पत्नी सविता कोविंद के साथ गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में माथा टेककर अरदास की। साथ गुरु नानक देव जी के हाथों लगाए गए बेर के वृक्ष के भी दर्शन किए। कोविंद ने देशवासियों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव की बधाई देते हुए गुरु साहिब को समूची मानवता की साझी धरोहर बताया। उन्होंने लोगों से गुरु नानक देव की शिक्षाओं पर अमल का आह्वान भी किया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच में आज से खुली सुनवाई

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जांच अब अगले चरण में पहुंच गई है। अमेरिकी संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में बुधवार और शुक्रवार को महाभियोग की जांच में खुले में सुनवाई होगी, जिसे टेलीविजन पर पूरा देश देखेगा। संसद के निचले सदन में 24 सितंबर से राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना

सत्ता का खेल ▶ राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

पार्टी ने दावा साबित करने के लिए कम समय दिए जाने को दी शीर्ष अदालत में चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजनीतिक उठापटक के अखाड़े के रूप में महाराष्ट्र ने मंगलवार को नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पहले शिवसेना की जिद और उसके बाद राकांपा और कांग्रेस की रणनीति में प्रदेश की राजनीति इतनी उलझी कि नतीजा आने के एक पखवाड़े बाद आखिरकार वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्यपाल के बुलावे पर भाजपा ने सरकार बनाने से इन्कार कर दिया और शिवसेना व राकांपा तय वक्त में बहुमत का आंकड़ा दिखाने में नाकाम रहीं। लिहाजा, मंगलवार दोपहर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद शाम तक राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी। इस दौरान विधानसभा निलंबित रहेगी। शिवसेना सरकार गठन के लिए कम समय दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन मंगलवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।

गृह मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपनी अनुशंसा में साफ लिखा कि वहां सरकार बनाने की हर कोशिश की गई, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना ही उचित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की बैठक के लिए ब्राजील रवाना होने वाले थे, लिहाजा तत्काल कैबिनेट बैठक बुलाकर सिफारिश पर मुहर लगा दी गई। दरअसल, पिछले महीने महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आया था और भाजपा-शिवसेना

मुंबई में मंगलवार को प्रेसवार्ता करते शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, साथ में आदित्य ठाकरे। एएनआइ

> हमने 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने हमें छह महीने का समय दे दिया। यह सच्चा हिंदुत्व नहीं है जब आप राम मंदिर का तो समर्थन करते हैं, लेकिन अपना वादा तोड़ देते हैं।
> – उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख

> महाराष्ट्र में सरकार गठन का दावा करने से पहले नीतियों और कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। कांग्रेस-राकांपा ने मंगलवार को साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया है।
> – शरद पवार, राकांपा प्रमुख

गठबंधन को संयुक्त रूप से बहुमत मिल गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद की जिद में मामला इतना उलझा कि नौ नवंबर को विधानसभा की अवधि खत्म होने तक बात नहीं बन पाई। उसके बाद राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास जरूरी 145 का आंकड़ा नहीं है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थीं कि भाजपा सरकार बनाएगी और मजबूरन शिवसेना साथ आएगी, लेकिन कर्नाटक की घटना से सतर्क भाजपा ने ऐसा नहीं किया।

राकांपा ने शाम तक कोशिश ही नहीं की : राज्यपाल ने दूसरा मौका 56 की संख्या लाकर दूसरे नंबर पर रही शिवसेना को दिया और उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन सोमवार शाम तक शिवसेना को कांग्रेस व राकांपा का लिखित समर्थन नहीं मिला। शिवसेना की ओर से और 24 घंटे का वक्त मांगा गया जिसे राज्यपाल ने नकार दिया और तीसरा मौका 54 सीटें वाली राकांपा को दिया गया जिसकी मियाद मंगलवार रात 8.30 तक थी, लेकिन राकांपा ने सुबह 11.30 पर ही राज्यपाल कार्यालय को सूचित कर दिया कि उन्हें और वक्त चाहिए।

कांग्रेस पार्टी में अब तक नहीं चुना जा सका है विधायक दल का नेता पेज>>3

देव दीपावली पर दीपों के आलोक में उभरा दिव्य लोक....

उत्तर प्रदेश स्थित धर्म नगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा पर देवों के वास की मान्यता मूर्तमान नजर आई। मंगलवार शाम के साथ आसमान में पूनम का चांद भी चमका और धरा दीपों के आलोक में नहाई। इस अवसर पर पंचगंगा घाट से मां गंगा का किनारा दीयों से जगमग हो उठा। मोहपाश में बांधने वाला दृश्य और विह्वल प्रकाश पुकार में उमड़ते लोगों ने निरंतर आकार पाते दिव्य लोक को निहारा। देश-दुनिया से जुटे सैलानियों ने इस नजारे को नयनों में समेटा और विभोर हो उठे। नवनीत रत्न पाठक

पांच फीसद पर सिमट सकती है विकास दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्थिक मोर्चे पर सरकार को कुछ और नकारात्मक खबरों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर होने में समय लग सकता है। यह बात देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शोध इकाई की तरफ से जारी रिपोर्ट इकोरैप में कही गई है।

मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर महज 4.2 फीसद रह सकती है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान विकास दर पांच फीसद से ज्यादा रहने का अनुमान नहीं है। अगले वर्ष से अर्थव्यवस्था में सुस्ती का माहौल खत्म होने और विकास दर के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

एसबीआइ की रिपोर्ट

- चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान 6.1 फीसद से घटाया
- बीती तिमाही में विकास दर सिर्फ 4.2 फीसद रहने का अनुमान

एसबीआइ के प्रमुख अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष के नेतृत्व में तैयार इस रिपोर्ट में सोमवार को औद्योगिक उत्पादन में 4.3 फीसद की गिरावट के आंकड़े को बेहद चिंताजनक बताया है। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर अनुमान को 6.1 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने के पीछे इसे एक बड़ी वजह बताया गया है। अगले वित्त वर्ष में सुधार के साथ जीडीपी की विकास दर 6.2 फीसद होने की बात कही गई है।

कृषि क्षेत्र में भी मुश्किल हालात : औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन की स्थिति भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहने का अनुमान है। इसके लिए मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश को एक बड़ी वजह बताया गया है। इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व पंजाब में खरीफ फसलों के उत्पादन पर भारी असर पड़ने की आशंका है।

ब्याज दरों में कटौती से भी हल नहीं पेज>>12

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का बेटा ईडी के रडार पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के पुत्र अबीर और उससे जुड़ी कंपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रडार पर हैं। अफसरों ने मंगलवार को बताया कि अबीर और उससे जुड़ी कंपनी 'नॉरिश ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा इस साल की शुरुआत में हासिल की गई 7.25 करोड़ रुपये की राशि की जांच के लिए ईडी ने फेमा के तहत मामला दर्ज किया है। इस जांच का मकसद यह पता लगाना है कि मॉरिशस स्थित 'सामा कैपिटल' से इस रकम को हासिल करने में फेमा का उल्लंघन तो नहीं किया गया था।

बताते हैं कि अबीर 'नॉरिश ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड' में निदेशक है। ईडी ने इस लेनदेन के संबंध में हाल में अबीर से पूछताछ भी की थी और उन्होंने जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच आगे बढ़ाने के लिए कुछ और लोगों को भी समन किया गया है। ज्ञात हो,

केंद्रीय एजेंसी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का है संदेह

अशोक लवासा के परिवार की मुश्किलें कुछ महीने पहले तब शुरू हुई थीं जब उनकी पत्नी नोवेल सिंघल लवासा कथित रूप से कर चोरी के आरोप में आयकर विभाग की रडार पर आ गई थीं। आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 10 कंपनियों में निदेशक पद पर आसीन होने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। अशोक लवासा के कुछ अन्य पारिवारिक सदस्य भी कर अधिकारियों की जांच के दायरे में हैं।

बता दें कि अशोक लवासा को केंद्रीय वित्त सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 23 जनवरी, 2018 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। हाल में हुए आम चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के साथ उनके मतभेद खुलकर सामने आए थे।

आज खुद पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर को आरटीआइ के दायरे में लाने का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर सूचना अधिकार कानून (आरटीआइ) के दायरे में आना चाहिए या नहीं इस मुद्दे पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआइ में पांच जजों की संविधान पीठ दोपहर दो बजे फैसला सुनाएगी। जस्टिस एनवी रमना, डीवाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना संविधान पीठ में शामिल अन्य जज हैं। फैसला सुनाए जाने की नोटिस मंगलवार दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई। संविधान पीठ ने चार अप्रैल को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई पूरी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोई भी अपारदर्शी प्रणाली नहीं चाहता। लेकिन, पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के महासचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट

और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की इस दलील को मानने से इन्कार कर दिया था कि मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर को आरटीआइ के दायरे में लाने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचेगा। इससे पहले सीआइसी ने भी अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआइ के दायरे में है।

क्या था दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला : 10 जनवरी, 2010 को अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सीजेआइ का दफ्तर आरटीआइ के दायरे में आता है। न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है। बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, जो उसे दी गई है। इस आदेश को तत्कालीन सीजेआइ केजी बालाकृष्णन के लिए निजी झटका माना गया था, जिन्होंने आरटीआइ के तहत जजों के सूचना देने से इन्कार कर दिया था।

इस तरह उठा मामला : सीजेआइ के दफ्तर को आरटीआइ के तहत लाने की मुहिम एससी अग्रवाल ने शुरू की थी। उनके वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा था कि हालांकि उच्चतम न्यायालय अपने मामलों पर फैसला नहीं देता है, लेकिन इस मामले में वह अनिवार्यता कानून के तहत सुनवाई कर रहा है। आरटीआइ के दायरे में जजों को लाने की अनिच्छा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या न्यायाधीश किसी दूसरे ब्रह्मांड से आते हैं?

लता मंगेशकर की हालत नाजुक

एंटरटेनमेंट, मुंबई : लिविंग लीजेंड स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। सोमवार रात सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया था।

विगत 28 सितंबर को 90 साल की हुई लता मंगेशकर का इलाज डॉक्टर पतित सम्धनी कर रहे हैं। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सोमवार को लता मंगेशकर के परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है। उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए एहतियातन उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों की कोशिश है कि फेफड़े में इंफेक्शन को फैलने से रोका जाए। गायिका होने की वजह से उनके फेफड़ों की क्षमता अच्छी है। इसी वजह से वह इस बीमारी से लड़ पा रही हैं। वह फाइटर हैं। लताजी की घर वापसी पर आप सबको सूचित किया जाएगा। (पेज-10 भी देखें)

बदलाव

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया नया सर्कुलर, 20 अंकों का होगा इंटरनल असेसमेंट, न्यूनतम छह अंक लाना होगा अनिवार्य

बदला परीक्षा पैटर्न, अब इंटरनल असेसमेंट भी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सत्र 2019-20 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। अब जिन विषयों में प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट नहीं होता था, उनमें से ज्यादातर विषयों में इंटरनल असेसमेंट को लागू कर दिया गया है, जोकि 20 अंक का होगा। बोर्ड परीक्षार्थियो को पास होने के लिए इसमें कम से कम छह अंक लाना अनिवार्य होगा।

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम और अधिकतम अंक लाने की सूची जारी कर दी है। सीबीएसई के सर्कुलर के मुताबिक प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा लेने के लिए बोर्ड द्वारा परीक्षक नियुक्त किया जाएगा, जबकि इंटरनल असेसमेंट स्कूल के शिक्षक ही करेंगे। बोर्ड से जारी सर्कुलर के मुताबिक दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को तो पास होने के लिए प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल और थ्योरी में मिलाकर 33 प्रतिशत अंक ही लाने होंगे, लेकिन 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में अलग-अलग 33 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं, 12वीं कक्षा में पहले हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों की परीक्षा 100 अंक की होती थी, जबकि अब इनमें भी 20 अंकों का इंटरनल असेसमेंट भी कराया जाएगा। जिन विषयों की थ्योरी परीक्षा 70 अंकों की होगी, उसमें न्यूनतम 23 अंक और 30 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा में नौ अंक लाने अनिवार्य होंगे।

16 से 30 दिसंबर तक होगी प्री-बोर्ड परीक्षा

सीबीएसई ने प्री- बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड ने 16 से 30 दिसंबर तक 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री-बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। विद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि प्री-बोर्ड परीक्षाएं दो के बजाय एक शिफ्ट में कराएं।

> बदले परीक्षा पैटर्न को लेकर सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। प्री-बोर्ड परीक्षा भी इसी पैटर्न पर ली जाएगी, ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो सकें।
> – संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई

सीबीएसई कराने जा रहा है आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता

सीबीएसई आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता कराने जा रहा है। दो चरणों में होने वाली इस परीक्षा में सभी स्कूलों के बच्चे भाग ले सकेंगे। पहले चरण में भाग लेने के लिए बच्चों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा। स्कूल अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

बोर्ड के मुताबिक, प्रतियोगिता में कक्षा आठ से दस तक के छात्र ही भाग ले सकेंगे। प्रथम चरण में यह प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर होगी। इसमें प्रत्येक विद्यालय के शीर्ष तीन छात्रों को दूसरे चरण के लिए चुना जाएगा। स्कूलों में होने वाली प्रथम चरण प्रतियोगिता 60 अंको की होगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 20 अंक के प्रश्न दैनिक जीवन से जुड़े, 20 अंक गणित को सीखने का आनंद और 20 अंक गणितीय क्षमता के आधार पर पूछे जाएंगे।

फिर से गैस चैंबर बना दिल्ली-एनसीआर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मौसमी उतार-चढ़ाव और कई दिनों की आंशिक राहत के बाद दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को वायु प्रदूषण फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया। पीएम 2.5 और 10 की मात्रा में भी खासा इजाफा देखने को मिला। हवा में पराली के धुएं की मात्रा बढ़ने से एयर इंडेक्स 400 पार यानी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। अगले दो दिन स्थिति और खराब होने की आशंका है। पराली के धुएं के साथ हवा की बदली दिशा और जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश की राजधानी फिर से गैस चैंबर बन गई है। नवंबर में यह दूसरा मौका है, जब ऐसे हालात बने हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर प्रदूषण से राहत मिलेगी।

> **425 पर पहुंचा दिल्ली में एयर इंडेक्स, अगले दो दिन स्थिति और खराब होगी**

दिल्ली के एयर इंडेक्स में मंगलवार को 65 प्वाइंट की वृद्धि हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर इंडेक्स के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 360 था, लेकिन मंगलवार को वातावरण में प्रदूषण की मात्रा तेजी से बढ़ी तो यह 425 पहुंच गया। इस श्रेणी की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। देश का सबसे प्रदूषित जिला पानीपत रहा, जहां एयर इंडेक्स 458 रिकार्ड हुआ।

दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स

गाजियाबाद	453
नोएडा	440
ग्रेटर नोएडा	436
दिल्ली	425
मानेसर	410
फरीदाबाद	406
गुरुग्राम	402

(नोट : सीपीसीबी के अनुसार)

हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के 740 मामले : दूसरी तरफ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर के मुताबिक सोमवार को हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के 740 मामले सामने आए हैं। इनकी संख्या भले कम है, लेकिन इस समय हवाओं की दिशा की वजह से पराली का धुआं दिल्ली आसानी से आ रहा है। मंगलवार को पराली ने दिल्ली को 25 फीसद तक प्रदूषित किया, जबकि आशंका है कि बुधवार को यह 22 फीसद तक दिल्ली को प्रदूषित करेगी।

दिन में भी दृश्यता प्रभावित

पराली के धुएं और स्थानीय स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर के आसमान पर स्मॉग की परत छाई हुई है। इसके चलते दिन के समय भी दृश्यता प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगले दो दिनों तक दिल्ली में हालात बद से बदतर होंगे। प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ेगा। इसके बाद 15 नवंबर से स्थिति में हल्का सुधार आने की संभावना है। सीपीसीबी के अनुसार, इस समय लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए और बाहर की गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए।